विचार बिन्दु

निरन्तर बदलने की इच्छा रखना एक ताकत होती है, चाहे इसकी वजह से कंपनी का एक बड़ा हिस्सा कुछ देर के लिए पूरी तरह से अव्यवस्थित क्यों ना हो जाए। –जैक वेल्व

विकसित राजस्थान: एक नारा नहीं, संकल्प है

राजस्थान का चरित्र अनेक युगों में परखा गया है: वीरता की गाथाएँ, किलों की शान, लोक कला की जीवंतता और मरुधर की कठोरता। पर आज का राजस्थान केवल अतीत की स्मृति नहीं है; यह बदलाव की राह पर अग्रसर एक क्षेत्र है, जहाँ परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। ''विकसित राजस्थान'' एक नारा नहीं, संकल्प है'' यह घोषणा केवल घोषणापत्रों में लिखे शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह हर नागरिक, हर संस्थान और सरकार के लिए स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए एक ऐसा लक्ष्य जो व्यवहार, नीति और प्रतिज्ञा में बदलकर जमीन पर दिखाई दे।

विकास की व्याख्या व्यापक होनी चाहिए। आर्थिक वृद्धि आवश्यक है, परंतु उसे जीवन की गुणवत्ता के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। विकास का असली माप केवल जीडीपी, निवेश या औद्योगिक उत्पादन नहीं; यह स्वास्थ्य की उपलब्धता, शिक्षा की गुणवत्ता, रोज़गार के स्थायी अवसर, पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक समावेशन से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सामने यह चुनौती है कि वह आर्थिक प्रगति को इस तरह संचालित करे कि उसका लाभ राज्य के दूर–दराज़ गाँवों, पिछड़े समुदायों और पारंपरिक कारीगरों तक पहुँच सके।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नीति–निर्माण में समावेशिता का मूल होना आवश्यक है। योजनाओं का स्वरूप सिर्फ शहरों या बड़े उद्योगों तक सीमित न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, महिला सशक्तिकरण और आदिवासी क्षेत्रों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखे। छोटे और मध्यम उद्यमों, विशेषकर हस्तशिल्प व कुटीर उद्योगों को सुव्यवस्थित बाजार, क्रेडिट सुविधा और डिजिटलीकरण के जरिए सशक्त किया जाना चाहिए। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें बुनाई, बांस व मिट्टी का कारीगरी शामिल है, केवल पर्यटन का आकर्षण नहीं यह स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार भी है। इन क्षेत्रीय क्षमताओं को आधुनिक विपणन, डिज़ाइन सहयोग और निर्यात–समर्थन से जोड़ना राज्यों के दीर्घकालिक विकास के लिए निर्णायक होगा।

जल और कृषि राज्य की सामाजिक–आर्थिक दृष्टि का केंद्र हैं। राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियाँ और जल–विभाजन इसे अनूठी चुनौतियाँ देती हैं। वर्षा पर आधारित पारंपरिक कृषि अब टिकाऊ नहीं रह गई है; इसलिए जल संरक्षण, सूक्ष्म–सिंचाई और फसल विविधीकरण जैसे उपायों को तात्कालिक प्रमुखता दी जानी चाहिए। कुएँ और तालाबों के पुनरुद्धार, भूजल पुनर्भरण और सामुदायिक जल संचयन जैसी स्थानीय पहलें जहां जल सुरक्षा बढ़ाएंगी, वहीं किसानों की आय में स्थिरता भी लाएँगी। कृषि मूल्य शृंखला में प्रोसेसिंग इकाइयों और प्रशीतन संरचना को जोड़ने से फसल–आधारित आय में वृद्धि संभव होगी। किसान उत्पादक संगठन और सहकारी व्यवस्थाओं को सशक्त बनाकर बाज़ार तक सीधी पहुँच सुनिश्चित करनी होगी ताकि मध्यस्थता कम हो और शोषण घटे।

शिक्षा और कौशल विकास के बिना स्थायी विकास की कल्पना अधूरी रहेगी। राजस्थान का युवा वर्ग राज्य का भविष्य है; इसलिए शिक्षा केवल साक्षरता तक सीमित न रहे, बल्कि व्यावहारिक कौशल, तकनीकी प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर प्रदान करे। विद्यालयों और प्रशिक्षण केन्द्रों में स्थानीय उद्योग, कुटीर और उच्च तकनीकी क्षेत्रों के साथ तालमेल होना चाहिए ताकि युवा रोजगार योग्य बनें। विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा व कौशल कार्यक्रमों को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि इनके सशक्त होने से परिवार और समुदाय दोनों का समग्र विकास होगा।

> **छोटे और मध्यम उद्यमों, विशेषकर हस्तशिल्प व कुटीर उद्योगों को सुव्यवस्थित बाजार, क्रेडिट सुविधा और डिजिटलीकरण के जरिए सशक्त किया जाना चाहिए। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, जिसमें बुनाई, बांस व मिट्टी का कारीगरी शामिल है, केवल पर्यटन का आकर्षण नहीं यह स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार भी है। इन क्षेत्रीय क्षमताओं को आधुनिक विपणन, डिज़ाइन सहयोग और निर्यात-समर्थन से जोड़ना राज्यों के दीर्घकालिक विकास के लिए निर्णायक होगा।**

ऊर्जा और पर्यावरणीय नीतियाँ भी राज्य के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। राजस्थान के विशाल सौर संसाधन और कुछ क्षेत्रों में पवन ऊर्जा का व्यापक संभावित भंडार इसे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बना सकता है। पर ऊर्जा नीति केवल उत्पादन तक सीमित नहीं होनी चाहिए; इसे वितरणीयता, स्थानीय उद्योगों के लिए सस्ती और विश्वसनीय आपूर्ति तथा ऊर्जा दक्षता के साथ जोड़ना होगा। छतों पर सौर पैनलों का प्रसार, सामुदायिक सौर परियोजनाएँ और ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगी। साथ ही, रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और जलवायु अनुकूलन उपायों को योजनाओं का अभिन्न अंग बनाना होगा ताकि विकास लंबी अवधि में टिकाऊ हो।

शहरीकरण की प्रक्रिया प्रबंधन हेतु स्मार्ट और समावेशी विचार आवश्यक हैं। शहरों का विस्तार अनियंत्रित न होकर नियोजित होना चाहिए; सार्वजनिक परिवहन, किफायती आवास और कचरा व जल प्रबंधन की समेकित नीतियाँ लागू हों। ऐतिहासिक शहरों और बाजारों के संरक्षित ढांचे को बरकरार रखते हुए नवप्रवर्तित सुविधाएँ विकसित करनी चाहिए ताकि सांस्कृतिक विरासत व आधुनिक सुविधा का संतुलन बना रहे। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं का असली उद्देश्य तकनीकी उन्नति के साथ नागरिक जीवन में वास्तविक सुधार लाना होना चाहिए, न कि केवल दिखावटी बुनियादी ढांचे का निर्माण।

शिल्प और पर्यटन के क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। पर्यटन पर निर्भर अर्थव्यवस्था मौसमी होती है; इसलिए शिल्पकारों को निरंतर और संगठित बाजार उपलब्ध कराना चाहिए। ब्रांडिंग, डिजिटलाईज़ेशन, कॉपीराइट सुरक्षा और निर्यात के साधन प्रदान करके कारीगरों की आय को स्थायी बनाया जा सकता है। पारंपरिक ज्ञान व कला का संरक्षण सिर्फ सांस्कृतिक कारण नहीं है, यह आर्थिक सुरक्षा का भी प्रश्न है। सतत पर्यटन मॉडल, जो स्थानीय समुदायों को सीधे लाभ पहुँचाए और पर्यावरण व सांस्कृतिक संवेदनशीलता का पालन करे, नीति का आधार होना चाहिए।

शासन–व्यवस्था में पारदर्शिता और स्थानीय भागीदारी विकास की कुंजी है। केंद्रीकृत नीतियों के साथ–साथ स्थानीय स्वायत्तता और निर्णय क्षमता बढ़ाने से नीतियाँ अधिक प्रभावी होंगी। ग्राम स्तर से लेकर नगर निगम तक बजट आवंटन और निगरानी में नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। ओपन डाटा नीतियाँ, डिजिटल सेवाएँ और मोबाइल–आधारित शिकायत समाधान तंत्र लोगों को सेवाओं से जोड़ने में सहायक होंगे। शासन में महिला और युवा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने से नीतियों में विविध दृष्टिकोण शामिल होंगे और वे ज़मीनी हक़ीक़तों के करीब रहेंगी।

विकास का सामाजिक और नैतिक आयाम नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। विकास की प्रक्रिया में पारस्परिक सम्मान, सामाजिक न्याय और नैतिक जिम्मेदारियों का समावेश होना चाहिए। शिक्षा में नागरिकता, नैतिक मूल्यों और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय समाज को संवेदनशील और जवाबदेह बनाता है। भ्रष्टाचार–रोधी उपाय, जवाबदेही के तंत्र और समाज में संवाद के अवसर निर्माण से दीर्घकालिक समृद्धि संभव है।

विकसित राजस्थान का संकल्प सिर्फ एक नीति दस्तावेज नहीं होना चाहिए यह व्यवहार स्तर पर जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। जब हर गाँव में जल–सुरक्षा होगी, हर युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल मिलेगा, हर कारीगर को उचित बाजार मिलेगा और शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधरेगी तब यह संकल्प पूरा कहा जाएगा। विकास की यह परिकल्पना सामूहिक प्रयत्नों से ही साकार होगी: सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और स्थानीय समुदायों के संयुक्त प्रयासों से। छोटे–छोटे व्यावहारिक कदम स्थानीय जल संचयन, कौशल प्रशिक्षण, शिल्प के डिजिटलीकरण और पारदर्शी प्रशासन मिलकर एक बड़े परिवर्तन की नींव रखते हैं।

राजस्थान का विकास इसलिए नारा नहीं, संकल्प होना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक समावेशी, हरित और सांस्कृतिक रूप से संपन्न प्रदेश छोड़ें। संकल्प तभी सार्थक होगा जब वह प्रतिदिन के कामों, नीतियों और सामुदायिक निर्णयों में उतर आए। तभी राजस्थान न सिर्फ अपने गौरवशाली अतीत पर गर्व करेगा, बल्कि भविष्य की चुनौतियों का सामना करते हुए एक समृद्ध और टिकाऊ प्रदेश बनकर उभरेगा।

–अतिथि संपादक,
अविनाश जोशी,
वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार

7.8 प्रतिशत की विकास दर: भारतीय अर्थव्यवस्था में नई उम्मीदों का उजाला

राम शर्मा

भारत की अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर्ज कर एक बार फिर दुनिया की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपना स्थान मजबूत किया है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान वास्तविक जीडीपी 81.36 लाख करोड रुपये रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह 75.46 लाख करोड रुपये थी। इस प्रकार वास्तविक वृद्धि 7.8 प्रतिशत रही। इसी अवधि में नाममात्र जीडीपी 10.3 प्रतिशत बढ़ी और वास्तविक सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई।

इन आंकडों को देखकर स्वाभाविक रूप से यह सवाल उठता है कि यदि अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से बढ़ रही है तो इसका असर रोजगार और आम आदमी की आय पर भी दिखाई देना चाहिए। लेकिन श्रम बाजार के आंकडे बताते हैं कि कहानी इतनी सीधी नहीं है। अप्रैल–जून 2026 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की समग्र बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत रही। शहरी बेरोजगारी दर 6.7 प्रतिशत और ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत रही। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी तिमाही में श्रमबल भागीदारी दर 54.6 प्रतिशत रही, जो पिछली तिमाही के 55.5 प्रतिशत से कम है।

यहीं से भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और रोजगार की वास्तविक तस्वीर के बीच का अंतर सामने आता है।

जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन रोजगार उसी अनुपात में क्यों नहीं?

आर्थिक विकास का अर्थ कुल उत्पादन और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि है। दूसरी ओर बेरोजगारी दर यह बताती है कि श्रम बाजार में उपलब्ध लोगों में कितने लोग काम की तलाश में हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। दोनों के बीच संबंध जरूर है, लेकिन यह संबंध हमेशा एक–से–एक नहीं होता।

भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान लगातार बढ़ रहा है। वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं, संचार, रियल एस्टेट और अन्य आधुनिक सेवाओं में उत्पादकता अधिक है। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम लोगों से अधिक आर्थिक मूल्य पैदा किया जा सकता है। इसलिए उत्पादन तेजी से बढ़ सकता है, लेकिन रोजगार उसी अनुपात में नहीं बढ़ता।

पहली तिमाही में वास्तविक जीवीए की वृद्धि 8.2 प्रतिशत रही। निवेश से जुड़े सकल स्थिर पूंजी निर्माण में करीब 11.9 प्रतिशत की वृद्धि और निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। सरकारी आंकडों के अनुसार विनिर्माण और सेवा क्षेत्र ने वृद्धि को महत्वपूर्ण आधार दिया।

यह अच्छी खबर है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से प्रश्न यह है कि नई पूंजी और नई तकनीक कितने नए रोजगार पैदा कर रही है।

बेरोजगारी दर का एक और महत्वपूर्ण पहलू

बेरोजगारी दर को अकेले देखकर रोजगार की पूरी तस्वीर नहीं समझी जा सकती। श्रमबल भागीदारी दर और वर्कर–पॉपुलेशन रेशियो भी देखना जरूरी है।

अप्रैल–जून 2026 में देश की श्रमबल भागीदारी दर 54.6 प्रतिशत रही, जबकि पिछली तिमाही में यह 55.5 प्रतिशत थी। महिला श्रमबल भागीदारी दर भी पिछली तिमाही के 34.7 प्रतिशत से घटकर 33.2 प्रतिशत रह गई। कुल वर्कर–पॉपुलेशन रेशियो 51.7 प्रतिशत रहा, जो पिछली तिमाही के 52.8 प्रतिशत से कम है। इसका अर्थ यह नहीं कि देश में रोजगार निश्चित रूप से घट गया है, क्योंकि तिमाही आंकडों पर मौसमी प्रभाव भी पडता है। लेकिन यह जरूर बताता है कि केवल बेरोजगारी दर को विकास का प्रमाण मानना पर्याप्त नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति रोजगार की तलाश ही छोड देता है तो वह बेरोजगारों की गणना में नहीं आता। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के श्रम बाजार की वास्तविक स्थिति समझने के लिए यह देखना आवश्यक है कि कितने लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं, कितने काम कर रहे हैं और किस प्रकार का काम कर रहे हैं।

56.6 करोड लोगों को रोजगार, लेकिन सवाल गुणवत्ता का

पीएलएफएस के अप्रैल–जून 2026 के आंकडों के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लगभग 56.6 करोड लोग रोजगार में थे। इनमें लगभग 40.2 करोड पुरुष और 16.4 करोड महिलाएं थीं।

यह संख्या भारतीय अर्थव्यवस्था के रोजगार के विशाल आकार को बताती है। लेकिन रोजगार की संख्या से अधिक महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता है।

क्या रोजगार नियमित है? क्या उससे परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं? क्या मजदूरी महंगाई की तुलना में बढ़ रही है? क्या सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध है? क्या युवा अपनी शिक्षा और कौशल के अनुरूप नौकरी पा रहे हैं?

इन सवालों के उत्तर आर्थिक विकास की वास्तविक गुणवत्ता तय करते हैं।

पीएलएफएस में एक सकारात्मक संकेत जरूर दिखाई देता है। नियमित वेतनभोगी कर्मचारियों का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में 15.5 प्रतिशत से बढ़कर 16.1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 48.9 प्रतिशत से बढ़कर 49.3 प्रतिशत हुआ है। माध्यमिक क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी भी बढ़ी है।

अर्थात रोजगार के ढांचे में कुछ सुधार के संकेत हैं, लेकिन अभी इसे व्यापक और पर्याप्त रोजगार सृजन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

प्रति व्यक्ति आय की तस्वीर क्या कहती है?

अब सवाल आता है प्रति व्यक्ति आय का। यहां भी यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल नहीं बढ़ रही।

सरकारी आंकडों के अनुसार 2025–26 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्तमान कीमतों पर लगभग 2.20 लाख रुपये के स्तर पर पहुंचने का पहला अग्रिम अनुमान था। 2024–25 में यह लगभग 2.05 लाख रुपये थी। स्थिर कीमतों पर भी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय औसत है, औसत परिवार की वास्तविक कमाई नहीं।

मान लीजिए किसी देश की राष्ट्रीय आय तेजी से बढ़ती है और उसका लाभ मुख्य रूप से बडे उद्योगों, उच्च कौशल वाले कर्मचारियों, पूंजी मालिकों और कुछ तेजी से बढ़ते क्षेत्रों को मिलता है। ऐसी स्थिति में प्रति व्यक्ति आय का औसत बढ़ सकता है, लेकिन बड़ी आबादी की वास्तविक आय में उतनी वृद्धि नहीं हो सकती। यही कारण है कि जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते आंकडों के बावजूद आम परिवार को आर्थिक दबाव महसूस हो सकता है।

वास्तविक आय और औसत आय में अंतर

प्रति व्यक्ति आय बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की आय उसी दर से बढ़ी है। यह राष्ट्रीय आय को कुल आबादी से विभाजित करके निकाला गया औसत है।

भारत जैसे विशाल और असमान अर्थव्यवस्था वाले देश में यह अंतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। एक ओर उच्च आय वाले पेशेवरों और पूंजी बाजार से जुडे लोगों की आय तेजी से बढ़ सकती है, वहीं दूसरी ओर असंगठित क्षेत्र के मजदूर, छोटे दुकानदार, ग्रामीण श्रमिक और निम्न आय वाले परिवारों की वास्तविक आय धीमी गति से बढ़ सकती है।

इसलिए आर्थिक विकास का अगला चरण केवल जीडीपी बढ़ाने का नहीं बल्कि वेतन और रोजगार की वृद्धि को जीडीपी वृद्धि के साथ जोडने का होना चाहिए।

7.8 प्रतिशत वृद्धि में उपभोग की भूमिका

पहली तिमाही में निजी अंतिम उपभोग व्यय में 7.1 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि हुई है। यह बताता है कि घरेलू मांग अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है। निवेश में भी लगभग 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

लेकिन यहां भी एक सवाल महत्वपूर्ण है–क्या उपभोग की वृद्धि व्यापक आय–वृद्धि से आ रही है या बचत में कमी और ऋण आधारित खर्च से?

यदि लोगों की आय तेजी से बढ़ती है तो उपभोग में वृद्धि टिकाऊ होती है। लेकिन यदि उपभोग का विस्तार महंगे कर्ज, क्रेडिट कार्ड या व्यक्तिगत ऋण के सहारे हो रहा हो तो लंबे समय में यह परिवारों की वित्तीय स्थिति पर दबाव डाल सकता है।

इसलिए जीडीपी के साथ घरेलू बचत, वास्तविक मजदूरी, उपभोक्ता ऋण और परिवारों की आय के आंकडों को भी समान महत्व देना होगा।

क्या 7.8 प्रतिशत की वृद्धि पर सवाल उठना चाहिए?

यह भी ध्यान रखना होगा कि 2026 में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए भारत ने नया आधार वर्ष 2022–23 अपनाया है। नई श्रृंखला में उत्पादक मूल्य सूचकांक सहित अधिक विस्तृत मूल्य आंकडों और अन्य प्रशासनिक स्रोतों का उपयोग किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे राष्ट्रीय आय के अनुमान अधिक व्यापक और आधुनिक बने हैं।

हालांकि इस नई पद्धति के बाद पिछले वर्षों के आंकडों में महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं और अर्थशास्त्रियों ने पारदर्शिता तथा पद्धति की अधिक जानकारी सार्वजनिक करने की मांग उठाई है। इसलिए 7.8 प्रतिशत की वृद्धि को लेकर राजनीतिक विवाद से अलग हटकर यह आवश्यक है कि राष्ट्रीय आय के आंकडों की पद्धति पूरी तरह पारदर्शी रहे।

यहां संतुलित दृष्टिकोण जरूरी है। उपलब्ध सरकारी आंकडों के आधार पर 7.8 प्रतिशत की वृद्धि को सीधे खारिज करना उचित नहीं होगा। लेकिन इसे अर्थव्यवस्था की समग्र समृद्धि का अंतिम प्रमाण मानना भी उतना ही गलत होगा।

असली चुनौती रोजगारयुक्त और समावेशी विकास की

भारत के सामने आज सबसे बडी आर्थिक चुनौती विकास दर को बनाए रखने के साथ–साथ उसे रोजगार में बदलने की है।

देश में हर वर्ष बडी संख्या में युवा श्रम बाजार में प्रवेश करते हैं। यदि आर्थिक वृद्धि मुख्य रूप से पूंजी और उत्पादकता आधारित रहती है और पर्याप्त श्रम–प्रधान रोजगार नहीं बनाती तो आने वाले वर्षों में रोजगार का प्रश्न और गंभीर हो सकता है।

भारत को ऐसे विनिर्माण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना होगा जो बडी संख्या में रोजगार पैदा कर सकें–कपडा, चमडा, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स, निर्माण और छोटे एवं मध्यम उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हो सकते हैं।

साथ ही छोटे कारोबारों को सस्ता ऋण, तकनीक, बाजार और औपचारिक वित्त उपलब्ध कराना होगा। कृषि से गैर–कृषि रोजगार की ओर संक्रमण को भी तेज करना होगा।

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती महिला रोजगार की है। कुल महिला श्रमबल भागीदारी अभी भी पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। यदि महिलाओं की शिक्षा, कौशल और रोजगार को अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा से जोडा जाए तो भारत की उत्पादन क्षमता और घरेलू आय दोनों में बडा सुधार हो सकता है।

विकास का अगला पैमाना क्या हो?

भारत के लिए 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि निस्संदेह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन किसी देश की आर्थिक सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि उसने कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन किया। असली सवाल यह है कि उस उत्पादन से कितने नए रोजगार बने, मजदूरी कितनी बढ़ी, परिवारों की क्रय शक्ति कितनी मजबूत हुई और विकास का लाभ समाज के कितने वर्गों तक पहुंचा।

आज भारत के सामने यही विरोधाभास है–मैक्रो अर्थव्यवस्था मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन माइक्रो स्तर पर रोजगार और आय की तस्वीर उतनी प्रभावशाली नहीं है।

इसलिए 7.8 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि को उत्सव का कारण जरूर माना जाना चाहिए, लेकिन इसे मंजिल नहीं समझना चाहिए। विकास की अगली कसौटी होगी–जीडीपी की तेज रफ्तार को व्यापक रोजगार, बढ़ती वास्तविक मजदूरी और अधिक समान आय–वितरण में बदलना।

यदि आर्थिक वृद्धि के साथ आम नागरिक की आय बढ़ती है, युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिलता है और महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ती है, तभी उच्च जीडीपी वृद्धि को वास्तविक आर्थिक समृद्धि कहा जा सकेगा। अन्यथा 7.8 प्रतिशत का आंकडा अर्थव्यवस्था की ताकत तो बताएगा, लेकिन समाज की आर्थिक खुशहाली की पूरी कहानी नहीं।

–राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

साक्षर राजस्थान के बिना विकसित राजस्थान का सपना अधूरा

राजेन्द्र जोशी

साक्षरता और विकास एक–दूसरे की धुरी हैं। जिस समाज में शिक्षा और साक्षरता का स्तर ऊंचा होता है, वहां विकास की गति भी तेज होती है। दुर्भाग्य से राजस्थान में पिछले एक दशक से साक्षरता सरकार की प्राथमिकताओं में दिखाई नहीं देती।

सरकारें विकास के नाम पर सड़क, नाली, पानी, बिजली और दूसरी बुनियादी सुविधाओं पर लगातार बजट खर्च करती हैं। इन सुविधाओं का निर्माण और विस्तार निस्संदेह जरूरी है, लेकिन यह भी समझना होगा कि यदि जनता शिक्षित और साक्षर होगी तो इन सुविधाओं के रखरखाव, उपयोग और विस्तार से जुडी अनेक समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। जागरूक और शिक्षित नागरिक सरकार की योजनाओं को समझेंगे, उनका सही उपयोग करेंगे और स्थानीय विकास में भागीदार बनेंगे। इसलिए साक्षरता केवल अक्षर ज्ञान नहीं, बल्कि विकास की बुनियाद है।

राजस्थान में दो दशक पहले साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ था। संपूर्ण साक्षरता अभियान ने गांव–गांव तक शिक्षा की अलख जगाई। लाखों लोगों को अक्षर ज्ञान से जोडा गया। इस अभियान ने न केवल साक्षरता प्रतिशत बढ़ाया, बल्कि शिक्षा के प्रति सामाजिक चेतना भी पैदा की। उस दौर में राजस्थान ने साक्षरता के क्षेत्र में देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। इस उपलब्धि को सतत अभियान में बदलना सरकार की जिम्मेदारी थी। यदि उस प्रयास को निरंतर आगे बढ़ाया जाता तो आज राजस्थान की तस्वीर कहीं अलग होती।

आंकडे बताते हैं कि 1991 से 2001 के दशक में राजस्थान ने साक्षरता के क्षेत्र में 22.48 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। यह एक तरह का 'क्वांटम जंप' था। इससे पहले 1981 से 1991 के दशक में साक्षरता वृद्धि मात्र 8.44 प्रतिशत थी। लेकिन 2001 से 2011 के बीच यह वृद्धि घटकर लगभग 6.03 प्रतिशत रह गई। सवाल यह है कि जिस राज्य ने एक दशक में इतनी बडी छलांग लगाई, वह अगले दशक में इतनी धीमी गति पर क्यों आ गया?

राजस्थान की स्थिति को हिंदी भाषी राज्यों के संदर्भ में देखें तो तस्वीर और भी चिंताजनक दिखाई देती है। मध्य प्रदेश ने 1991–2001 के दशक में साक्षरता में 19.44 प्रतिशत की वृद्धि की और 2001–2011 के दशक में भी 6.52 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। उत्तर प्रदेश ने 2001–2011 के दौरान 12.36 प्रतिशत की वृद्धि की। बिहार ने भी साक्षरता में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए 63 प्रतिशत से अधिक का स्तर हासिल किया। छत्तीसगढ़ ने भी 1991–2001 के दौरान बड़ी छलांग लगाई और बाद के दशक में अपनी स्थिति को आगे बढ़ाया।

दूसरी ओर, राजस्थान में पिछले डेढ़ दशक से साक्षरता को लेकर कोई स्पष्ट और दीर्घकालिक राज्य स्तरीय एजेंडा दिखाई नहीं देता। पिछले दशक में देश के कई राज्य पूर्ण साक्षरता की दिशा में आगे बढ़े और कुछ राज्य पूर्ण साक्षरता की श्रेणी तक पहुंच गए। राजस्थान इन प्रयासों से सीखने के बजाय जैसे अपनी गति से ही चल रहा है। विडंबना यह है कि हम दूसरों को सिखाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनसे सीखने की तैयारी भी नहीं दिखती।

राजस्थान में स्वतंत्र साक्षरता निदेशालय कार्यरत है। निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी हैं, बड़ी संख्या में शिक्षा अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं और सभी जिलों में जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारियों की व्यवस्था है। यानी प्रशासनिक ढांचा मौजूद है, मानव संसाधन मौजूद है और सरकार के पास काम करने के लिए तंत्र भी उपलब्ध है। फिर सवाल उठता है कि इस पूरी व्यवस्था का उपयोग साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रभावी ढंग से क्यों नहीं हो रहा?

आज नवभारत साक्षर कार्यक्रम और डिजिटल साक्षरता जैसे कार्यक्रम चल रहे हैं। डिजिटल साक्षरता समय की आवश्यकता है, लेकिन राजस्थान की जमीनी हकीकत को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्य के अनेक गांवों में आज भी बिजली और इंटरनेट की सुविधा पर्याप्त नहीं है। जिस व्यक्ति को कागज और कलम के माध्यम से अक्षर ज्ञान तक नहीं मिला, उससे सीधे डिजिटल साक्षरता की अपेक्षा करना कितना व्यावहारिक है? डिजिटल साक्षरता का पहला आधार भी तो सामान्य साक्षरता ही है।

राजस्थान के सामने एक और बडी चुनौती क्षेत्रीय असमानता है। कोटा से जैसलमेर तक साक्षरता प्रतिशत में बडा अंतर है। जिलों के बीच ही नहीं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में भी साक्षरता की स्थिति अलग–अलग है। इसके साथ महिला और पुरुष साक्षरता के बीच का अंतर भी चिंता का विषय है। जब तक महिलाओं को समान रूप से शिक्षा और साक्षरता से नहीं जोडा जाएगा, तब तक राजस्थान की समग्र साक्षरता दर में अपेक्षित सुधार संभव नहीं है।

जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों से इसमें देरी हुई और अब 2026 के बाद इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए वर्तमान दशक में राजस्थान की साक्षरता कितनी बढ़ी, इसका प्रमाणिक आकलन विस्तृत जनगणना आंकडे आने के बाद ही हो सकेगा। हालांकि बीच–बीच में हुए नमूना सर्वेक्षणों के आंकडे यह संकेत जरूर देते हैं कि राजस्थान की साक्षरता दर में अपेक्षित तेजी नहीं आई है।

सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, उसे शिक्षा और साक्षरता को अपने मुख्य एजेंडे में शामिल करना होगा। राजस्थान ने कभी साक्षरता के क्षेत्र में देश को राह दिखाई थी। अब आवश्यकता है कि उसी ऊर्जा और संकल्प को फिर से जगाया जाए। साक्षरता निदेशालय को केवल प्रशासनिक ढांचे तक सीमित रखने के बजाय उसे स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजट, समयबद्ध कार्ययोजना और परिणाम आधारित जिम्मेदारी दी जानी चाहिए।

78 वर्ष बाद भी यदि राजस्थान की बडी आबादी अक्षरों के आलोक से पूरी तरह नहीं जुड पाई है तो यह केवल सरकार की नहीं, पूरे समाज की चिंता का विषय है। लेकिन नेतृत्व सरकार को ही करना होगा। जिस दिन राजस्थान सरकार साक्षरता को सडक, बिजली, पानी और आवास की तरह विकास की अनिवार्य प्राथमिकता मानेगी, उसी दिन बदलाव की वास्तविक शुरुआत होगी।

राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाना है तो केवल भौतिक ढांचा खड़ा करना पर्याप्त नहीं होगा। उस ढांचे को समझने, संभालने और आगे बढ़ाने वाला साक्षर और जागरूक समाज भी तैयार करना होगा। आखिर सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राजस्थान कब पूर्ण साक्षर होगा; असली सवाल यह है कि राजस्थान पूर्ण साक्षर हुए बिना विकसित कैसे होगा?

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद–साहित्यकार

लेखक पिछले चार दशक से शिक्षा–साक्षरता के क्षेत्र में कार्यरत रहे है।

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 11 सितम्बर, 2026

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, शुक्रवार, विक्रम संवत 2083, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र दिन 1:16 तक, साध्य योग सायं 5:02 तक, नाग करण प्रातः 8:57 तक, चन्द्रमा आज सायं 7:08 से कन्या राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–कन्या, मंगल–मिथुन, बुध–कन्या, गुरू–कर्क, शुक्र–तुला, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह

मेष: परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। पारिवारिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या–वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

वृष: व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित

मेष

परिजनों के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। पारिवारिक मामलों में दुविधा बनी रहेगी। आपसी ईर्ष्या–वैमनस्यता के कारण परेशानी हो सकती है। खान–पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

वृष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सुख–सुविधाएं बढ़ेगी।

कन्या

आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। धन हानि का भय है। घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक कारणों से भागदौड़ रहेगी।

तुला

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृश्चिक

व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मकर

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

कुंभ

परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

मीन

विवादित मामलों का निपटारा हो सकता है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच–विचार हो सकता है।